

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 14 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 345

महत्वपूर्ण एवं खास

भूपेंद्र बने गुजरात के 17वें सीएम

गांधीनगर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य के शीर्ष पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के दो दिन बाद, भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात के राजभवन में एक सादे समारोह में भूपेंद्र पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं की मौजूदगी में राज्यपाल ने भूपेंद्र पटेल को राज्य के नए मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटेल गुजरात में पाटीदार समुदाय में एक मजबूत प्रभाव रखते हैं, जिसे बीजेपी ने आगामी चुनाव जीतने के लिए तैयार किया है। बताया गया कि बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक्शन मोड में रेलवे

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर भारतीय रेलवे ने तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड-19 के प्रभाव और महाराष्ट्र सरकार के भूमि अधिग्रहण के मसले को लेकर प्रोजेक्ट काम पहले ही सुस्त पड़ा हुआ है। इस बीच रेलवे ने काम में तेजी के लिए नई तकनीकों का सहारा लेने जा रहा है। रेलवे ने 508 किलोमीटर लंबे रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पुलों के निर्माण के लिए एक खास इंतजाम किया है। रेलवे की ओर से एक विशालकाय मशीन को लॉन्च किया गया है। यह मशीन इस रेल कॉरिडोर पर तेजी से पुलों को बनाने का काम करेगी। यह मशीन दूसरी मशीनों की अपेक्षा में तेजी से काम करेगी। जिससे मुंबई-अहमदाबाद रूट पर बनने वाले पुलों का निर्माण जल्दी हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में से एक लार्सन एंड टुब्रो ने इस मशीन को तैयार किया है। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसकी मदद से रेलवे के रूट को कम समय में बेहतर तरीके से बनाया जा सकेगा। रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड (एनएचएसआरएल) को सात हाई स्पीड रेल (एएएसआर) कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा है, जिसमें चेन्नई-बैंगलोर-मैसूर और मुंबई शामिल हैं। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कुल लागत 1.08 लाख करोड़ है।

कॉलेजियम की गुवाहाटी उच्च न्यायालय में तीन न्यायाधीशों के नामों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इसकी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने नौ सितंबर को हुई एक बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों को सोमवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जिन नामों को मंजूरी किया गया है उनमें न्यायमूर्ति सीमिता सैकिया, न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति और न्यायमूर्ति एस हुकातो सू शामिल हैं। सीजेआई रमण के अलावा न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में फैसला लेता है।

चार मजिला इमारत ढही, मलबे में दबे 2 बच्चों समेत 3 लोगों को निकाला गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली के सब्जी इलाके में एक 4 मजिला इमारत गिर गई है। ऐसे में आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आंशका है कि अभी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। ये सब्जी दिल्ली के मलका गंज इलाके के पास है। मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में दबे दो बच्चों समेत तीन लोगों को बाहर निकाला गया है, इनमें से एक बुरी तरह जखमी बताया जा रहा है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक दूध की डेरी होने की बात भी सामने आई है। दरअसल, ये घटना राजधानी दिल्ली के मलका गंज इलाके की है। जहां इस हादसे की चपेट में एक कार भी आ गई है। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया शुरू कर दिया गया है।

पेगासस विवाद में सरकार पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट

पर्सनल फोन्स की हैकिंग हुई या नहीं? फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी विवाद पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह जानना चाहता है कि आखिर इस मामले में अब तक सरकार ने क्या किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर उसने इस मामले में एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं किया। इसके साथ ही अदालत ने पेगासस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।



सरकार ने अदालत के सवालों पर कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से हम इस पर एफिडेविट दाखिल नहीं कर सकते हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले पर कोई बात एफिडेविट के जरिए नहीं कही जा सकती। एफिडेविट दाखिल करना और फिर उसे सार्वजनिक किया जाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने

खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर नहीं करेगी क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला शामिल है। इसके बाद चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि अगर सरकार अतिरिक्त हलफनामा नहीं दाखिल करती है तो न्यायालय को इस मामले में अपना आदेश जारी करना होगा। लगभग डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। उन्होंने साफ कहा कि हम आतंकियों को यह जानने का मौका नहीं

दे सकते हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर अदालत ने सरकार से असहमति जताते हुए कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को समझते हैं और हमने यह भी कहा कि सरकार को इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां हमने इस पर जवाब मांगा है कि निजी तौर पर जिन लोगों के फोन टैपिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं बचाव सही है या फिर गलत। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से सवाल

किया, पिछली बार भी आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क उठाया था और हमने कहा था कि इस मामले में कोई भी किसी भी तरीके से दखल नहीं दे सकता। हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर लोगों के फोन हैक किए जाने को लेकर जवाब मांग रहे हैं। जस्टिस कांत ने सरकार के जवाब पर ऐतराज जताते हुए कहा, हमें सिर्फ कुछ लोगों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन्स को हैक किए जाने की चिंता है। आखिर किस एजेंसी के पास ऐसी क्षमता है और उसे ऐसा अधिकार दिया गया था या नहीं। कई लोगों का कहना है कि इसके जरिए उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी निजता का हनन हुआ है तो यह गंभीर मसला है और हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं। हम इस मसले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमिटी का गठन करेंगे।

कर्नाटक में भीषण हादसा: जीप ने लॉरी को मारी टक्कर, आठ लोगों की दर्दनाक मौत

चिक्कबल्लपुर (आरएनएस)। कर्नाटक के चिक्कबल्लपुर जिले में रविवार को एक जीप और ट्रक की भयंकर भीड़ंत हो गई, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो व्यक्तियों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जीप और ट्रक की टक्कर आमने-सामने से हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि यह एक्सीडेंट जीप ड्राइवर की लापरवाही और नियंत्रण खोने की वजह से हुआ है।

चिक्कबल्लपुर पुलिस ने कहा कि जीप में कथित तौर पर 15 लोग सवार थे। जीप श्रीनिवासपुर तालुक के रायलपाडु से चिंतामणि तालुक की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। ट्रक में कम से कम आठ लोगों की

मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, जीप में दो बच्चे भी सवार थे। सभी पीड़ित चिक्कबल्लपुर जिले के ग्रामीण इलाकों से थे। ट्रक से टक्कर की वजह से जीप हवा में उछल गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक स्थानीय ने बताया कि गांवों में बस सुविधाओं की कमी की वजह से जीप बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षा मानदंडों के अनदेखी करते हुए ले जाती है और आरटीओ कभी-कभार ही ओवरलोडिंग पर कार्रवाई करता है। जद (एस) के विधायक एम कृष्ण रेड्डी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना के लिए आरटीओ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।

नायडू ने भारत में सौर प्रकाश वोल्टीय सेल और मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ाने का किया आह्वान

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज राज्यों का आह्वान किया कि वे सौर प्रकाश वोल्टीय सेल और मॉड्यूल के लिये निर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करें, ताकि देश में उनके उत्पादन में तेजी आये।



सौर सेल और मॉड्यूल जैसे पुर्जों के लिये आयात पर भारत की भारी निर्भरता को मद्देनजर रखते हुये उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों के सक्रिय सहयोग से सौर ऊर्जा क्षेत्र में 'आत्म निर्भरता' बहुत

महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने इस सम्बंध में उद्योग जगत के छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। अगले कुछ वर्षों में नवीकरणीय क्षेत्र में भारत की विकास-क्षमता के हवाले से नायडू ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे पास प्रशिक्षित कार्यबल का अभाव हमारे विकास की राह में रोड़ा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यबल का कौशल बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देने में निवेश किया जाये। इस दिशा में आधुनिक

उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर दिया कि सौर, पवन और छोटे पन बिजली संयंत्रों जैसी हरित ऊर्जायें हमारी बढ़ती ऊर्जा मांगों का कारण विकल्प हैं। 'ऊर्जा अंतरण' के क्षेत्र में विश्व में कार्यबल को सक्षम बनाया जाये। उन्होंने 'सूर्य मित्र' योजना का भी उल्लेख किया। पुदुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेश के पांडिचेरी युनिवर्सिटी में 2.4 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करते हुये

सीआरपीएफ बंकर के पास मिले छह ग्रेनेड, अलर्ट पर सेना

श्रीनगर में बड़े हमले की साजिश नाकाम:

श्रीनगर (आरएनएस)। श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेमिना इलाके में आज संधिध परिस्थितियों में सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के चिक एक्शन टीम के बंकर के पास छह ग्रेनेड मिले। इस घटना के बाद सेना अलर्ट हो गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ग्रेनेड देखे जाने के तुरंत बाद ही इसकी सूचना बम निष्क्रिय दस्ते को दी गई। यह सभी चीन निर्मित ग्रेनेड हैं। जवानों की सूझबूझ से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने सभी ग्रेनेड अपने कब्जे में ले लिए हैं।



कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन ऐसे हाईब्रिड आतंकियों पर अब पूरी निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर समेत घाटी में पिछले कुछ सप्ताह में साफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ये घटनाएं ऐसे पिस्तौल धारी युवकों की ओर से करवाई गई हैं जो सुरक्षा एजेंसियों की सूची में आतंकी के रूप में नहीं हैं। ऐसे आतंकियों को खोजना मुश्किल होता है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हाईब्रिड आतंकियों को टाइट हाईब्रिड आतंकियों को ट्रैक करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये वारदात को अंजाम देने के बाद अपने सामान्य

करने के बाद नए टास्क का इंतजार करते हैं। इस बीच वह अपने सामान्य कामकाज को करने लगते हैं। रविवार को श्रीनगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर अशीद अहमद पर भी इसी तरह का हमला हुआ जिसमें एक आतंकी ने पिस्तूल से अशीद अहमद पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि आतंकी की पहचान कर ली गई है। गौर हो कि हाईब्रिड आतंकी वे हैं जो सुरक्षाबलों की सूची में नहीं हैं। ये स्लीपर सेल की तरह ही इन युवाओं को पाटवडाम आतंकी बनाया गया है। लेकिन इन्हें बरगलाकर इस तरह का कट्टरपंथी बनाया जाता है कि हैडलर की ओर से सौंपे गए टास्क के तहत हमले कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने सामान्य कामकाज में जुट जाते हैं। इन्हें पहचानने में दिक्कत आती है।

एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी चौहान सरकार

मुख्यमंत्री ने किया 110 करोड़ लागत की गारमेंट इकाई का भूमि-पूजन

टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा तथा जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। राज्य सरकार कुछ ही दिनों में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर रही है। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ उद्यमिता, स्व-रोजगार



को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार की अपर संभावनाएँ हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। पिछले 17 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद 384 इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे

11 हजार करोड़ पूंजी निवेश और 22 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संकट की परिस्थितियों के बावजूद औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48 प्रतिशत, भूमि आवंटन में 32 प्रतिशत, पूंजी निवेश में 33 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में जल आपूर्ति परियोजना कार्य का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तागोव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक बैरिसिया श्री विष्णु खत्री, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के प्रबंध संचालक शिवराम कृष्ण गणपति तथा अधिकारी उपस्थित थे।

तीन चौथाई से अधिक महिलाएँ करेंगी कार्य- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित यह इकाई 10 एकड़ भूमि पर बनेगी। कंपनी द्वारा

110 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जाएगा, जिसमें 4 हजार से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्लांट में तीन चौथाई से अधिक महिलाएँ कार्य करेंगी। इस इकाई से ही लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र 146 हेक्टेयर भूमि पर विकसित है। टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा में 154 भूखण्ड हैं, जिनमें उद्योग स्थापना पर 800 करोड़ पूंजी निवेश की संभावनाएँ हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज का निधन

दिमाग में चोट के चलते दो महीने से ये अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 80 वर्षीय ऑस्कर फर्नांडीज का पिछले दो महीने से मंगलुरु के येनोपोया अस्पताल में इलाज चल रहा था। 18 जुलाई को वह घरेलू कामकाज करते हुए चोटिल हुए थे। इसके चलते उन्हें सिर में अंदरूनी चोटें आई थीं। 19 जुलाई को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां 27 जुलाई को ब्रेन सर्जरी के बाद खुल के थक्के हटाए गए थे। इसके बाद से उनकी लगातार डायलिसिस चल



रही थी। कांग्रेस ने उनकी मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। गांधी परिवार के करीबियों में रहे शामिल- मूल रूप से उडुपी के रहने वाले ऑस्कर फर्नांडीज 1980 में पहली बार एमपी बने थे। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान सड़क, यातायात और हाईवे, श्रम और रोजगार, सांख्यिकी और प्रोग्राम इंफ्लोमेटेशन और विदेश मामलों के कैबिनेट और राज्य मंत्री थे। ऑस्कर फर्नांडीज इंदिरा गांधी के परिवार के बेहद करीबी थे।

